Skill Development Programme

For Answer Writing

Governance (Model Answer)

DATE : 18-May-2018 **TIME : 11:45 am**

मुख्य परीक्षा

प्रश्न- **'सूचना का अधिकार, 2005' प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए।** (150 शब्द)

'Right to Informantion, 2005' ensures transparency and accountability in the governance. Evaluate this statement. **(150 Words)**

MODEL ANSWER

उत्तर- **भूमिका :** सूचना का अधिकार अधिनियम, ऐसी सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करता है, जो किसी सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा धारित अथवा उसके नियंत्रण में है। इसमें कार्य, दस्तावेज, अभिलेखों को देखने, दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने तथा किसी भी कामकाज का निरीक्षण करने का अधिकार आम नागरिक को प्रदान किया है। यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) में लागू है।

विशेषताएँ-

1. इसमें समस्त संवैधानिक कानून, सरकारी आदेश से गठित संस्थाओं के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों को भी सम्मिलित किया गया है।
2. अपीलीय स्तर पर शिकायतों के निपटारे के लिए राज्य सूचना आयोग एवं केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई।

आर.टी.आई. के माध्यम से पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना-

इसके माध्यम से विभागीय गतिविधियों के विषय में लोगों को अधिक से अधिक जानने का तथा सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। जिसने प्रशासन में भ्रष्टाचार को कम कर पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है।

भारत में सिविल प्रशासन की संरचना और कार्यप्रणाली ब्रिटिश काल में बनाए गए नियमों, कानूनों पर आधारित है। जिसमें जवाबदेहिता का अभाव रहा है, परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात अच्छे शासन की अवधारणा तथा आर.टी.आई. के अधिकार के अंतर्गत स्मार्ट शासन के रूप में जवाबदेहिता के विकास पर बल दिया जाने लगा है।

सीमाएं-

1. लोकप्राधिकारी शब्द को लेकर विवाद रहा है।
2. अनेक संवैधानिक ईकाईयों जैसे- हाईकोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि ने स्वयं को आर.टी.आई. के अंतर्गत लोकप्राधिकारी मानने से इंकार किया है।

अंत में सुधारात्मक उपाय/सुझावों को शामिल करते हुए संक्षिप्त व संतुलित निष्कर्ष दें।

* * *

GS World Committed To Excellence